सर्किट हाउस में ओडीओपी की बैठक में एमएसएमई राज्य मंत्री और प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन, लेदर पार्क की भी दमदार पैरवी होगी

जूता मंडी होगी आबाद, लैम्को होगा शुरू

आगरा | वरिष्ठ संवाददाता

शाहगंज में पचकुइयां के पास बदहाल चल रही जूता मंडी (जूता प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र) को जल्द ही पूरी तरह से आबाद किया जाएगा। इसके लिए दुकानों की कीमतें 5000 वर्ग फीट से कम कर 1000 रुपये के आसपास लाई जाएंगी। यही नहीं 19 साल से बंद चल रहे यूपी लैदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन (लैम्को) को फिर से खोला जाएगा। फतेहपुर सीकरी रोड पर बंद पड़े मेगा लेदर पार्क के प्रोजेक्ट की भी दमदार पैरवी होगी।

देश की 65 फीसदी जूता खपत एवं लगभग 25 फीसदी निर्यात में सहयोग देने वाले छोटे कारीगरों को सहयोग देने की खातिर यह घोषणा शुक्रवार को सर्किट हाउस में ओडीओपी की बैठक में की गई। क्योंकि पीएम मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यह घोषणा करने वाले प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री चौ. उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल और विशेष सचिव गौरव दयाल का कहना है कि छोटे उद्योगों के दम पर ही यह लक्ष्य पूरा होगा।

जमीन की पेशकशः प्रमुख सचिव ने कहा कि एक्सप्रेसवे के पास 20 हेक्टेयर जमीन पड़ी है। यदि चाहें तो वहां स्टोन एवं मार्बिल हैंडीक्राफ्ट का हब बनाया जा सकता है। एक्सप्रेस वे से आने वाले लोग यहां एक ही जगह पर चीजें खरीद पाएंगे।

शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक करते एमएसएमई राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, विशेष सचिव गौरव दयाल, डीएम एनजी रवि कुमार व अन्य। • हिन्दुस्तान

परेशानी सुनी

उप आयुक्त उद्योग शरद टंडन ने बताया कि प्रदेश सरकार की अहम एक जनपद एक उत्पाद योजना को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जगह जगह मीटिंग आयोजित की जा रही हैं। चयनित उत्पाद के समक्ष आ रही दिक्कतों के साथ ही क्षेत्र के दूसरे अन्य उत्पाद के स्टेकहोल्डरों से विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के स्टोन एवं मार्बिल हैंडीक्राफ्ट के उद्यमियो से बातचीत की गई। उनकी दिक्कतों को सुना गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति रही।

मंत्री ने पढ़ाया पाठ

एमएसएमई मंत्री ने बैठक के दस बजे की बजाए एक बजे शुरू होने को लेकर समय प्रबंधन का पाठ पढ़ाया। बोले वे तो इस बैठक के लिए साफा पहन कर, तिलक लगा कर सुबह साढे नौ बजे से ही तैयार हैं। पता चला कि अधिकारी ही नहीं आए हैं। आगाह किया कि भविष्य में यह लेट लतीफी न हो।

केले बेच रहे उस्ताद

एक उद्यमी ने प्रमुख सचिव से कहा कि 60 हजार कारीगर पच्चीकारी से जुड़े है। दो साल से काम ठप है। कारीगरों को केले बेचकर, सब्जी के ठेल लगाकर गुजारा करना पड रहा है। दुनिया में केवल आगरा में ही मार्बल पच्चीकारी की कला है, जिसे ट्रेनिंग और वित्तीय मदद देकर बचा सकते हैं।

1.58 करोड़ का चेक दिया

आयोजन के दौरान एसाइड योजना के प्रोजेक्ट ट्रेड सेंटर, टेस्टिंग लैब में प्रदेश सरकार के सहयोग की राशि का 1.58 करोड का चेक प्रदान किया गया। एफमक के अनुसार अभी भी काफी राशि मिलना शेष है।

भ्रांतियां दूर हों

स्टोन एवं मार्बेल हस्तशिल्प सेक्टर की जीएसटी एचएसएन कोड की दिक्कत, सब्सिडी मिलने में दिक्कत, कुशलता की कमी आदि को प्रमुख सचिव ने पूरे धैर्य के साथ सुना। बोले, पहले तो सभी सेक्टरों को एक साथ विलय कर स्टोन एंड मार्बिल हैंडीक्राफ्ट नाम रख दिया जाए। उद्यमियो और अवार्डी शिल्पियो से कहा कि वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और मार्केट बना सकते है।

रखी गई यह दिक्कतें

- जूता दस्तकारों के समक्ष सही दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता की दिक्कत। तैयार माल को बेचने की दिक्कत
- आगरा में एड हॉक मोरेटोरियम लगा होने के कारण ओडीओपी योजना कारगर भूमिका में नहीं आ पा रही है।
- जूता उद्योग का कच्चा माल 18 फीसदी टैक्स पर और एक हजार रुपये तक का तैयार माल पांच फीसदी टैक्स पर
- मेगा लेदर पार्क की कमजोर पैरवी के कारण यह प्रोजेक्ट लटका, जूता इकाइयों का विस्तार रुका, नुकसान
- श्रम विभाग के नियमों के कारण कला के पिता से पुत्र को हस्तांतरण में बाधा की समस्या को दूर कराया जाए
- लोन आवेदकों को बैंक टरका देते हैं। राशि बड़ी हो तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। कहां से हो कारोबार
- स्टोन एवं मार्बिल हस्तशिल्प पर टैक्स की दर 12 फीसदी है। जबकि पहले यह कर मुक्त था। कारोबार ठप
- विदेशी खरीदारों के समक्ष आईटीसी रिटर्न की समस्या होने के कारण बिक्री में बड़ी गिरावट हो चुकी है

प्रमुख सचिव के आश्वासन

- डीएम से कहा, कमेटी बनाकर जूता मंडी की दुकानों की सही रेट तय करें। जरूरत पड़े तो शासन से मदद होगी .
- मौके से ही पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी को कॉल किया। वास्तविक दिक्कत सॉल्यूशन पर रिसर्च कराएंगे
- जीएसटी परिषद को पत्र लिख कर समस्या को रखा जाएगा। कच्चे माल के साथ तैयार जूते की दिक्कत दूर होगी
- यूपीएसआईडीसी के शीर्ष अधिकारी को कॉल कर फाइल निकलवाई। मजबूत पैरवी के लिए काम किया जाएगा।
- इंडस्ट्री के सुझाव पर सरकार तैयार। मसौदा पेश करें। एसपीवी बनाएं, दस फीसदी लगाएं, 90 फीसदी सरकार से लें।
- उद्योग विभाग को दी लोन आवेदन की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी। फिर भी दिक्कत तो आरबीआई से करेंगे शिकायत
- जीएसटी परिषद को लिख कर इस समस्या का हल कराने के लिए कहेंगे। सरकार की तरफ से दमदार पैरवी होगी
- इस मामले में भी जीएसटी परिषद से वैकल्पिक व्यवस्था मानने के लिए कहा जाएगा। यह कार्य तुरंत किया जाएगा।

यह दिए गए सुझाव

- एक अरसे से पचकुइया स्थित मंडी बदहाल है। वीरान पड़ी है। दुकानें बाजार दर पर मिलें तो आबाद हो जाएगी
- आगरा के फुटवियर उत्पादन की श्रेणी बदल कर व्हाइट में ले जाना ताकि एडहॉक मोरेटोरियम से फर्क न पड़े
- कच्चे माल पर टैक्स की दर को पांच फीसदी लाया जाए। एक हजार रूपये से ऊपर के जूते को भी पांच फीसदी में
- सीकरी रोड के मेगा लेदर प्रोजेक्ट की दमदार पैरवी की जाए। क्योंकि इसमें पर्यावरण का कोई उल्लंघन नहीं है
- पाठ्यक्रम का हिस्सा बने ओडीओपी। ताकि बच्चों को सातवीं-आठवीं क्लास से ही रोजगार की तरफ जोड़ा जाए
- एससी/एसटी हब की तर्ज पर सरकार गारंटी ले और छोटे उद्यमियों को आसान शर्त पर लोन दिलाया जाए
- स्टोन एवं मार्बिल हस्तशिल्प को कर मुक्त किया जाए। या फिर इसे न्यूनतम टैक्स के स्लैब में लाया जाए
- विदेशी खरीदारों को जब तक एयरपोर्ट पर रिफंड की व्यवस्था नहीं है, तब तक खरीद में राहत दी जाए

Scanned by CamScanner

'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) योजनान्तर्गत
एक दिवसीय वर्कशाप का आयोजन
ODOP Ecosystem (लेदर तथा मार्बल इनले) के अध्ययन
में किये जा रहे सर्वे के सम्बन्ध में स्टेकहोल्डर्स से चर्चा
मुख्य अतिथि - श्री चौ. उदयभान सिंह जी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, उ.प्र. सरकार
अतिथि - डा. नवनीत सहगल (IAS)
लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
आगरा
10.00
Bisleri
Himalayan

Shot on OnePlus
By SS